









# संपादकीय

## कानून की रक्षा... करने की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती सिर्फ़ कानून की व्याख्या करने की नहीं है। बल्कि उसके सामने कानून के राज को बेमायने कर देने की एक विशेष राजनीतिक परियोजना से कानून की रक्षा करने की चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अदालत की इजाजत के बुल्डोजर से देश में किसी प्रकार के निर्माण को ढाहने पर दो हफ्तों के लिए जो रोक लगाई है, वह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक की इस अवधि के लिए जो दिशा-निर्देश तय किए हैं, कानून के राज में वे आम चलन का हिस्सा होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माणों को तोड़ना कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि बुल्डोजर के जरिए संदिग्ध अभियुक्त के मकान को गिराने का चलन फैल गया है। देखा यह गया है कि संबंधित अभियुक्त अगर मुस्लिम समुदाय का हुआ, तो ऐसी कार्रवाई तुरंत की जाती है। चलन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और धीरे-धीरे अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसे अपना लिया गया। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ऐसे कदमों के जरिए एक तरह का राजनीतिक संदेश भेजने की कोशिश की गई है। बुल्डोजर को ऐसा सियासी सिंबल बना लिया गया है कि अमेरिका स्थित हिंदुत्व समर्थक गुटों ने 15 अगस्त के समारोहों का आयोजन बुल्डोजर रख कर करते देख गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अदित्यनाथ के समर्थक उनका उल्लेख 'बुल्डोजर बाबा' कह कर करते रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती सिर्फ़ कानून की व्याख्या करने की नहीं है। बल्कि उसके सामने कानून के राज को बेमायने कर देने की एक विशेष राजनीतिक परियोजना से कानून की रक्षा करने की चुनौती है। कोर्ट के जज इस बात से नाराज थे कि उनकी विपरीत टिप्पणियों के बावजूद नेता यह रहे हैं कि बुल्डोजर तो चलते रहेंगे। क्या कोर्ट ऐसे नेताओं की जबाबदेही तय कर सकते कि स्थिति में है? क्या वह उसकी टिप्पणियों, आदेश और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा कर ऐसी सजा देने को तत्पर है, जो दूसरों के लिए मिसाल बने? दरअसल, 'बुल्डोजर राज' पर न्यायिक हस्तक्षेप बहुत देर से हुआ है। अब तक ये बीमारी बहुत गहरे फैल चुकी है। आरंभ में ही न्यायपालिका ने इसे रोक दिया होता, तो बात यहां तक पहुंचती ही नहीं।

# आलेख

# अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा...

अजय दीक्षित

चौदह वर्ष के बनवास के बाद रावण को मार कर और सीता को मुक्त करवा कर जब राम जी वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कहा कि प्रजा को विश्वास दिलवाने के लिए उन्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी ! यद्यपि यह नारी का अपमान है, ऐसा बहुत से राम भक्त भी मानते हैं। कोरोना काल में कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने एक नई आबकारी नीति बनाई जिसमें शराब कारोबारियों को ज्यादा कमीशन भिला। इस ज्यादा कमीशन का कुछ हिस्सा रिश्वत के तौर पर अरविन्द केजरीवाल और उसके साथियों को भिला, ऐसा आरोप ई.डी. लगा रही है। इसी सिलसिले में पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह फिर अरविन्द केजरीवाल केद हुए। लम्बे समय बाद काफी कावृनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें जमानत भिली। केजरीवाल की जमानत के साथ कई शर्तें हैं। केजरीवाल जब तक वे जेल में रहे उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। परन्तु बाहर निकलने के बाद अचानक उन्होंने त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। 17 सितम्बर को आतिशी को अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया। इसी दिन एल.जी. के सामने अरविन्द

केजरीवाल ने त्यागपत्र दे दिया। आतिशी से मुख्यमंत्री के दावेदारों में कई नाम चर्चा में थे। परन्तु शायद आतिशी के मृद व्यवहार के कारण लगा कि वह महिला होने के नाते अफसरों से आसानी से काम करा सकेंगी। वैसे वे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने इंग्लैण्ड से एम.ए. किया है। सन् 2013 से वे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं। परन्तु अरविन्द केजरीवाल ने एक और घोषणा की है कि वे चुनाव के दौरान जनता के पास जायेंगे और कहेंगे कि यदि वे बेईमान हैं तो उन्हें वोट न दें और यदि जनता समझती है कि वे ईमानदार हैं तो वोट दें। अब बड़ा घपला है। मान लें कि जनता अरविन्द केजरीवाल को फिर से चुन लेती है तो फिर कौन सी अदालत बड़ी है? जनता की? या कानून की? असल में दिल्ली में असली पावर एल.जी. के पास रहती है। तो क्या केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी की स्वीकृति एल.जी. से ली थी या नहीं? फिर यदि नहीं भी ली थी तो एल.जी. और केन्द्रीय गृह मंत्रालय क्या कर रहा था कि दिल्ली में यह घपला चलता रहा? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? भाजपा जो आज इतनी आलोचना कर रही है, वह क्यों नहीं तभी सक्रिय हुई। फिर यह बात भी लीगल एक्सपर्ट बतलाएंगे कि यह मामला ई.डी. और सी.बी.आई। दोनों में कैसे चल रहा है। यदि गोवा के इलेक्शन में इतना पैसा लगा तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? तभी क्या गोवा की पुलिस या गोवा की इंटेरिजेंस को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया, या संजय सिंह या अरविन्द केजरीवाल के पास से एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ? तो फिर पैसा कहां गया? असल में यदि अग्नि परीक्षा में केजरीवाल सफल हो जाते हैं और जनता उन्हें फिर से चुनती है तो क्या होगा? यह यक्ष प्रश्न है।

**दुनिया चाहती है, मेक इन इंडिया.....**

श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

देश ने 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' पहल के 10 साल परे होने का उत्सव मनाया, जो गोजगाप मज़न करने



के रूप में नया उत्साह दिया है, जो घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात में भी योगदान दे रहा है। यह रोमांचक यात्रा एक कठिन समय में शुरू हुई थी, जब निर्णय लेने में अक्षम कांग्रेस सरकार की नीतिगत निष्क्रियता और कुशासन के कारण घरेलू निवेशक निराश थे। अर्थव्यवस्था निम्न स्तर पर थी, आत्मविश्वास टूट चुका था, सुर्खियों में नियमित रूप से भ्रष्टाचार के घोटालों का जिक्र होता था, मुद्रास्पर्मिति बढ़ रही थी, ब्याज दरें अधिक थीं और रुपये का पूर्वानुमान अनिश्चित था। दुर्भाग्य और निराशा की भावना को समाप्त करने के लिए, भारतीय मतदाताओं ने निर्णयक तौर पर पीएम मोदी के पक्ष में मतदान किया। हमारे प्रधानमंत्री भारत के लिए एक दृष्टिकोण लेकर आए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बने। वे चाहते थे कि भारत हमारे युवाओं को रोजगार और अवसर प्रदान करे, इस तथ्य की पहचान करते हुए कि विनिर्माण भारत की सफलता की गाथा के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं परिस्थितियों में, प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत की। दस साल की यात्रा उल्लेखनीय रही है, लेकिन यह मोदी सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी और परिवर्तनकारी बदलावों के बिना संभव नहीं हो पाती। पहलों में जीएसटी, दिवालियापन संहिता और कई

अन्य सुधार शामिल हैं। कारोबार करने में आसानी में सुधार के लिए, 42,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया और मामूली अपराधों के लिए आपराधिक दंड प्रदान करने वाले 3,700 प्रावधानों को विभिन्न कानूनों से हटा दिया गया, ताकि छोटे व्यवसायों को उत्पीड़न से बचाया जा सके। भारत ने विश्व बैंक की व्यापार करने की रिपोर्ट में 2014 के 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान पर पहुंचकर अपनी श्रेणी में तेजी से सुधार किया। सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल ने नौकरी की इच्छा रखने वाले कई लोगों को नौकरी प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे इस वर्ष जून में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,40,803 हो गई है, जिससे निवेश में बढ़ोत्तरी और 15 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। ये स्टार्टअप देश में नवाचार इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं तथा स्वच्छता, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्य बर्बादी को कम करने, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करने और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे क्षेत्रों से जुड़े जलवायन मुद्दों का समाधान करने पर कार्य कर रहे हैं। सरकार के विशेष ध्यान का एक अन्य क्षेत्र है - 11 औद्योगिक गलियारों का विकास। कार्यक्रम के तहत 20 औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं, जो इन गलियारों को भारत के विनिर्माण

विकास का प्रमुख आधार बनाने में मदद करेंगे इनमें से चार स्मार्ट शहर पहले ही निवेश के आकर्षण केंद्र बन गए हैं, जहां अवसंरचना के साथ विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मंजूरी उपलब्ध है। 1.7 लाख करोड़ रुपये के संभावित निवेश के लिए पहले ही प्रतिबद्धता व्यक्त की जा चुकी है, जो 80,000 लोगों को प्रत्यक्ष और इससे भी अधिक संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा।

सरकार की पीएलआई योजनाएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, वाहन, वस्त्र और चिकित्सा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि इन क्षेत्रों में निरंतर विकास के लिए इको-सिस्टम तैयार किया जा सके और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। पीएलआई योजनाओं के परिणामस्वरूप 1.32 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और विनिर्माण उत्पादन में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस पहल के माध्यम से 8.5 लाख से अधिक रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर सुजित हुए हैं। प्रधानमंत्री की अवसंरचना से जुड़ी पहल भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक और प्रोत्साहन है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा करने के अलावा, अवसंरचना विकास औद्योगिक गतिविधि के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है। आज भारत में

एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का एक विशाल और बढ़ता हुआ नेटवर्क है। विश्व स्तर के नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जबकि नए प्रेट कॉरिडोर का निर्माण-कार्य प्रगति पर है। भारत को निवेश के लिए एक बहुत ही आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। देश 4डी लाभ की पेशकश करता है - प्रधानमंत्री मोदी का निर्णायक नेतृत्व; हमारे युवा, प्रतिभाशाली, कुशल भारतीयों का जनसांख्यिकीय लाभांश; 140 करोड़ भारतीयों द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न की जाने वाली मांग; एक जीवंत लोकतंत्र, जो निवेशकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करता है तथा कानून का शासन, जो कभी भी किसी के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। 4-डी भारत में निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत ही प्रभावी परिदृश्य प्रस्तुत करता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आज अपने व्यवसाय के विस्तार का सुनहरा अवसर मिल रहा है। निवेशक समुदाय में कई प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। कई प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहे हैं, जो निवेश करने और भारतीय विकास गाथा में भाग लेने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। विदेशी सरकारें और वैश्विक सीईओ भारत में अवसरों पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं। कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। दुनिया अब भारत को एक विनिर्माण गंतव्य के रूप में देख रही है। इस दिलचस्पी का मुख्य कारण है - भारत का अपना प्रतिस्पर्धी लाभ और अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों की मजबूत स्थिति। आज मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, आर्थिक विकास मजबूत है और मोदी सरकार कठोर राजकोषीय अनुशासन का पालन कर रही है। युद्ध और अनिश्चितता से ग्रस्त वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में यह और भी सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की पहलों ने भारत को 2014 के दुनिया की **पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाएँ** वाले देशों में से एक माने जाने की अप्रिय स्थिति से ऊपर उठने में मदद की है और अब देश दुनिया के शीर्ष पांच देशों में से एक बन गया है। वास्तव में, मैके इन इंडिया जैसी प्रधानमंत्री मोदी की पहलों ने पिछले 10 वर्षों को एक परिवर्तनकारी दशक बनाने में योगदान दिया है जिसे कांग्रेस शासन के खोए हुए दशक की तुलना में एक बड़ी छलांग कहा जा सकता है।

फिर पुराना दौर लौट आए, यह भी नहीं लगता

श्रुति व्यास

श्रीनगर में चुनाव का भूत सिर चढ़ कर बोल रहा है। चारों ओर राजनीति पर चर्चा है। शहर के रहवासी अपनी शिकायतों की फेहरिस्त सुनाने की बजाए कौनसा उम्मीदवार सबसे बेहतर है, इस बारे में बातचीत करने और कयास लगाने में अधिक मशगूल हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। हर मिनट एक नई बात, एक नई अटकल सामने आ रही है। हवा भी गर्म है। इस बार सितंबर में घाटी आश्र्यजनक और असामान्य रूप से गर्म है। लोग नतीजों का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। उत्सुकता है और उत्तेजना भी। लोगों में चुनावों में भागीदारी का जज्बा है। चुनावी माहौल वैसा ही है जैसा कि आजकल होता है लङ् शोरगुल कम है और यह अनुमान लगाना मुश्किल कि किसके पक्ष में मूँह है। घाटी का कौना-कौना रंग-बिरंगा और खूबसूरत है। माहौल आकर्षक और लुभावना है। मिसाल के तौर पर डल झील पर 22 सितंबर की दोपहर नेशनल काव्हेंस ने शिकाया रैली की। सामान्यतः डल झील और उसके आसपास बड़ी संख्या में पर्यटक जमा रहते हैं। लेकिन आज वहां चुनावी हलचल और उससे जुड़ा तामझाम नजर आ रहे थे। श्रीनगर में ऑटोरिक्षाओं पर झड़े और पोस्टर नहीं होते बल्कि डल झील में तैर रहे शिकायों पर लगे होते हैं। सुबह 11 बजे, डल झील के घाट नंबर 7 पर

रेलों में भाग लेने वाल आर उसको खबर देने वाल लोग जमा हो चुके हैं। लाल, सफेद और नीले रंग के शिकारों पर नेशनल काफ़ेंस का लाल झँडा लहरा रहा था और उन पर पार्टी के सदस्य, कार्यकर्ता, समर्थक और मीडियाकर्मी सवार होते हुए। साफ लगा आज शिकारों का सफर अलग ही होना है। उमर अब्दुल्ला, दिल्ली में नेशनल काफ़ेंस के तेजतरर चेहरे आगा सैयाद रुहुल्ला मेहंदी, अपने बचपन के मित्र शम्मी ओबेराय, अपने दोनों पुत्रों जमीर और जहीर, जादिमल से पार्टी के उम्मीदवार तनवीर सादिक और अन्य लोगों के साथ हैवन इन लेक' (झील में जन्मत) नाम के शिकारे पर सवार हैं। आसमानी नीले रंग के इस शिकारे में वार्कइ उसके नाम के अबुरुप सारी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं। लकड़ी की दो कुर्सियां और एक मेज है, जिस पर प्लास्टिक के पूल सजे हुए। एक पिकनिक बास्केट है जिसमें डेविडओफ कॉफी और अन्य छोटी-मोटी चीजें रखी हैं। ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला जहां भी जाते हैं, कॉफी उनके साथ होती है। बताया जाता है कि इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान उनका पहला काम होता है अपने लिए एक कप स्ट्रांग काफी तैयार करना। ब्लू टोकाई उनकी पहली पसां है। उसकी महक और स्वाद का आनंद लेकर ही वे अपना चुनाव अभियान शुरू करते हैं। हो सकता है यह उनका अंधविश्वास हो, इसे वे भाग्यशाली मानते हों या यह दिखावा हो। बहरहाल

स्वच्छ है, उसकी कालजयी खूबसूरती में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के चलते गिरावट है। लेकिन राजनेता पहले जैसे ही हैं। तीसरी पीढ़ी के नेता उमर अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अतीत में अटकी हुई है। वे खोखले हो चुके अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठ रहे हैं जब कि लोग महांगाई और बेरोजगारी से परेशान हाल हैं। यह शिकायत मुझे कश्मीर में हर जगह पुरुषों और महिलाओं से सुनने को मिली। लेकिन उमर और उनकी पार्टी अतीत की बातों में ही उलझी हुई है। जब मेरा शिकाया बाकी कफिले से अलग होकर दक्षिण दिशा में मुँइकर वापिस घाट 7 की ओर बढ़ने लगा, तब मुझे शिकारों की एक और पक्की नजर आई जिसमें इंजीनियर राशिद का प्रचार किया जा रहा था। उसमें तेज संगीत के साथ दूसरे वैरेटिव की चर्चा थी। सवाल है करीब तीन दशकों तक चली हिंसा और फूँड़ राजनीति के बाद, अनुच्छेद 370 हटाने और अमन-शांति के आभास के बीच, भविष्य कैसा नजर आ रहा है? मैं जब शिकारे से उतर रही थी और डल झील सूरज की पीली रोशनी से चमक रही थी तब मेरे मन में विचार आया कि क्या अभी भविष्य बूझना संभव है? अभी नहीं। चुनावी जोश और उत्सुकता का यह दौर नए भविष्य का इस्तकबाल करे, यह भी नहीं लगता तो फिर पुराना दौर लौट आए, यह भी नहीं लगता।

# के जरीवाल की बड़ी सियासी कवायद

राज कुमार सिंह

तेरह सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पाने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ देने का इशारा जताकर सबको चौंका दिया है। इस्तीफ़ देने के लिए उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत और उस पर जश्न के चार दिन बाद का समय चुना है। उन्होंने घोषणा की है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ दे देंगे और जब तक दिल्ली के मतदाता चुनावी जनादेश के जरिये उन्हें ईमानदार नहीं मान लेते, तब तक दोबारा पट नहीं संभालेंगे। वह चाहते हैं कि महाराष्ट्र और झारखण्ड के साथ दिल्ली में भी नवंबर में चुनाव कराए जाएं। तब तक आप का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री पद संभालेगा। जाहिर है, अनेक सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इससे आम आदमी पार्टी, दिल्ली, विपक्ष और देश की राजनीति पर क्या असर होगा? यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ देने का ख्याल कथित शराब नीति घोटाले में लगभग 177 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद क्यों आया? उनके विरोधी तो इस्तीफ़ को मांग गिरफ्तारी के समय से परिस्थिति पर सो जमानत चलेगा। गठबंधन चुनाव में सभी संघरफतारी सहानुभूति पार्टी को अब के मेहनत द्वारा सिर्फ़ केवल विधानसभा अगले साल पार्टी के मुद्दों-नामों के नतीजे हैं। पिछले गुजरात, जमाने वाले साल के चुका हैं से आप हैं। कभी

क गए, जहां उन्हें निराशा हाथ इस्तीफे का निर्णय केजरीवाल ने लिया, चुनावियों और सभावनाओं विचार करके ही लिया है। मिल गई, पर मुकदमा लंबा भी नहीं बात, आप और कांग्रेस में बाबजूद दिल्ली में लोकसभा नगातर तीसरी बार भाजपा का सीटें जीत जाना बताता है कि से केजरीवाल को ज्यादा नहीं मिली है। मतलब, उनकी और मेहनत करने की जरूरत है। केजरीवाल पदमुक्त होकर ज्यादा ने की स्थिति में होंगे। जब न वाल के गृह राज्य हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में भी फरवरी में ही चुनाव होंगे, तब आक्रामक रणनीति और नए की दरकार है। लोकसभा चुनाव भाजपा की सीमाएं उजागर कर रहे हैं। पंजाब में प्रचंड बहुमत तथा वा जैसे सुदूर राज्यों में भी पैर कोशिश से उसे गठन के दस दर ही राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल हरहाल, पिछले चुनावी नतीजों कांग्रेस, दोनों ने सबक सीखा कांग्रेस समेत तमाम दलों को भ्रष्ट



कि अन्य गैर-भाजपाई दलों को साथ लिए बिना राष्ट्रीय राजनीति संभव नहीं, तो विपक्ष भी समझ गया है कि दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत बाले दल को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। पिछले साल विपक्षी दलों के 'ईंडिया' ब्लॉक के बैनर तले एकजुट होने का ही परिणाम रहा कि 2014 और 2019 में अकेले दम बहुमत हासिल करने वाली भाजपा आज बहुमत के लिए तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड व लोक जनशक्ति पार्टी पर निर्भर हो गई है। इस बीच विपक्षी नेताओं, खासकर मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध ईडी और मुश्किलें भी बढ़ीं। कथित शराब नीति घोटाले में पहले उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तो पिछ सांसद संजय सिंह और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए। बेशक तीनों अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं, पर केजरीवाल की छवि पर भाजपा को सवालिया निशान लगाने का मौका मिल गया है। आप ने दिल्ली में पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनावी वायदों को पूरा किया है, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष है। ऐसे में, शराब घोटाले के आरोपों के दाग के साथ विधानसभा चुनाव में जाने का जोखिम अनुरागी रहा है। हर राज्य में ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने पद छोड़कर अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया है। जेपी, बाल ठाकरे से लेकर सोनिया गांधी तक ऐसे कदावर नेताओं के अनेक उदाहरण हैं। केजरीवाल भी रोजमर्ग के सरकारी कामकाज से दूर रहकर अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने पर जोर लगाएंगे। किसी भी राज्य में अपनी या विपक्ष की जीत को नैतिक विजय बताते हुए आक्रामक केजरीवाल ठहरी हुई आप को राष्ट्रीय राजनीति में गति देना चाहेंगे। हालांकि, उनकी राह आसान नहीं है। बातचीत के बावजूद कांग्रेस ने हरियाणा में







